

कोरोँव तहसील (जनपद प्रयागराज) में महिला साक्षरता का परिवर्तित प्रतिरूप का एक भौगोलिक अध्ययन

दिलीप कुमार ¹, डॉ० अमित सचान ²

¹शोध छात्र, भूगोल विभाग, पी०एस०एम०पी०जी० कॉलेज, कन्नौज

²प्रोफसर, भूगोल विभाग, पी०एस०एम०पी०जी० कॉलेज, कन्नौज

(सम्बद्ध छत्रपतिशाह जी महाराज वि०वि० कानपुर, उ०प्र०)

सारांश:

इस शोध पत्र में कोरोँव तहसील, जनपद प्रयागराज में महिला साक्षरता की वर्तमान स्थिति, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। महिला साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का महत्वपूर्ण साधन है। 2001 और 2011 की जनगणना के तुलनात्मक आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और लैंगिक अंतर घटा है, फिर भी यह अंतर अब भी गंभीर चुनौती बना हुआ है। अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक रूढ़िवादिता, गरीबी, विद्यालयों की दूरी, परिवहन और सुरक्षा की कमी, तथा पारिवारिक दृष्टिकोण महिला शिक्षा की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं। सरकारी योजनाएँ जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है, किन्तु उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। महिला साक्षरता में सुधार का सीधा प्रभाव परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता पर पड़ता है। इसलिए, कोरोँव तहसील में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना न केवल शैक्षिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बहुआयामी रणनीतियों, लैंगिक समानता की दिशा में मानसिकता परिवर्तन, और संसाधनों की सुलभ उपलब्धता के माध्यम से इस क्षेत्र को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द: महिला साक्षरता, लैंगिक समानता, सामाजिक-आर्थिक विकास, कोरोँव तहसील

प्रस्तावना

भारत में महिला साक्षरता का महत्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास, लैंगिक समानता, और आर्थिक प्रगति का आधार भी है। पिछले कुछ दशकों में देश की महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब भी पुरुष साक्षरता दर से पीछे है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14 प्रतिशत और महिलाओं की 65.46 प्रतिशत थी। यह अंतर केवल आंकड़ों का अंतर नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में मौजूद गहरी असमानताओं का द्योतक है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी, और बेहतर जीवन-निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

महिला साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को न केवल बुनियादी पढ़ने-लिखने की क्षमता मिलती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक नेतृत्व में भागीदारी के अवसर भी बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है।” यह कथन आज भी पूर्ण

रूप से प्रासंगिक है क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे अपने परिवार, समाज और देश को प्रगति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं जैसे रूढ़िवादी सोच, गरीबी, असुरक्षा की भावना और शिक्षा के संसाधनों की कमी जो इस दिशा में प्रगति की गति को धीमा करती हैं।

कोराँव तहसील, जनपद प्रयागराज का एक प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र, इस समस्या का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की सामाजिक संरचना, परंपरागत मान्यताएँ और आर्थिक स्थिति महिला शिक्षा के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करती हैं। कई परिवार आज भी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति उदासीन हैं और उन्हें घर के कार्यों या प्रारंभिक आयु में विवाह के लिए तैयार किया जाता है। स्कूलों की दूरी, परिवहन सुविधाओं का अभाव और महिला सुरक्षा की गारंटी का न होना, बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण है। इन परिस्थितियों में महिला साक्षरता की स्थिति सुधारने के लिए न केवल सरकारी प्रयास, बल्कि सामाजिक सोच में भी परिवर्तन आवश्यक है।

सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसे प्रयास भी शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। फिर भी, इन नीतियों के पूर्ण लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, और लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा

भारत में महिला साक्षरता पर किए गए अधिकांश शोध इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ओझा (1988) और सिंह (1979) जैसे विद्वानों ने जनसंख्या भूगोल और कृषि भूगोल के अध्ययन में स्पष्ट किया है कि महिला शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक गतिशीलता में सकारात्मक बदलाव लाती है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर हुई जनगणना (2001, 2011) के आँकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि यद्यपि महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है, फिर भी यह पुरुष साक्षरता दर से पीछे है। इस अंतर का कारण शिक्षा तक सीमित पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संसाधनों की कमी है।

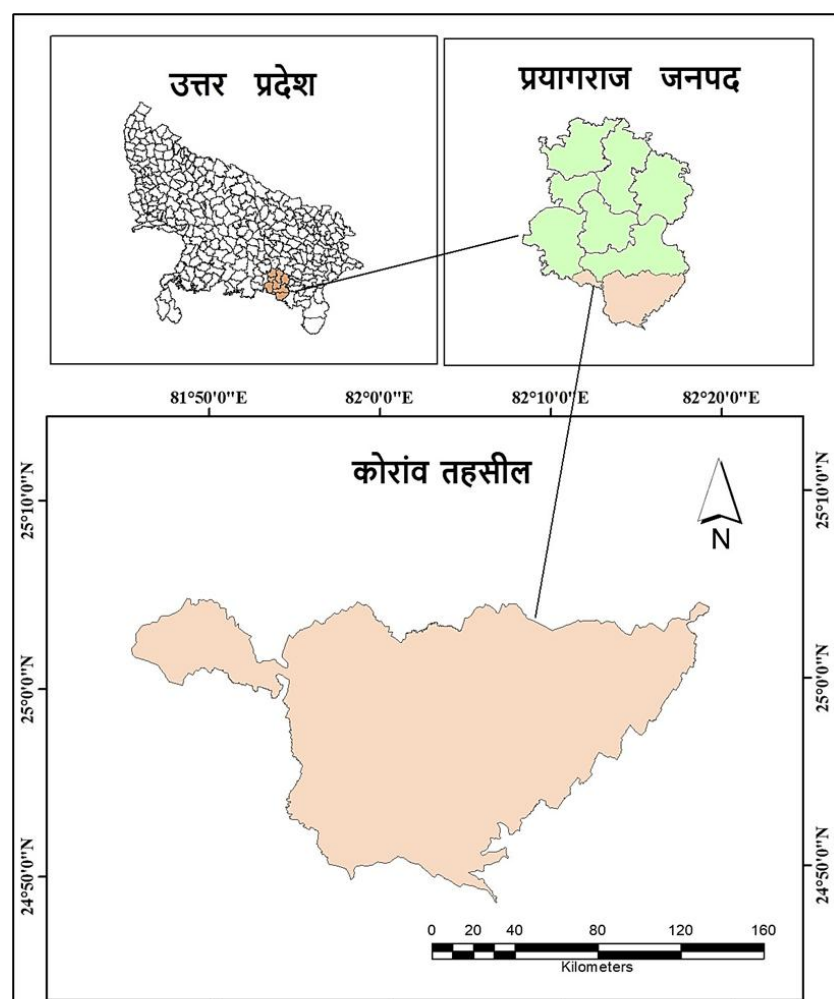
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शोध यह साबित करते हैं कि महिला साक्षरता में सुधार से न केवल पारिवारिक आय और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और पोषण स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूनेस्को की रिपोर्टों में बार-बार यह उल्लेख किया गया है कि महिला साक्षरता, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है। कई अध्ययन इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदि लड़कियों की शिक्षा को माध्यमिक और उच्च स्तर तक ले जाया जाए, तो बाल विवाह, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कमजोर है। दूबे एवं सिंह (विभिन्न वर्षों में) ने यह पाया कि पिछड़े और अर्ध-पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, जैसे गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक दबाव और महिला सुरक्षा की कमी, लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों की सीमित उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर प्रेरणा के अभाव के कारण भी कई परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा में निवेश नहीं करते।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही हैं। फिर भी, विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक मानसिकता में बदलाव और आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता है। कोराँव तहसील जैसे क्षेत्रों में, जहाँ भौगोलिक दूरी, परिवहन सुविधा की कमी और पारंपरिक मान्यताएँ महिला शिक्षा की राह में बाधा हैं, वहाँ बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है ताकि शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र कोराँव तहसील जनपद प्रयागराज के आठ तहसीलों में से एक है। जिसका अक्षांशीय विस्तार 24°50' उत्तर और 25°10' उत्तरी अक्षांश



तालिका 1: Study Area(GIS)

तथा देशान्तरी विस्तार 81°50' पूर्व से 82°50' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कोराँव तहसील के पूर्व में मिर्जापुर जनपद की सीमा लगती है एवं द0 में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, प0 में बुन्देलखण्ड का क्षेत्र तथा उत्तर-प0 में प्रयागराज की सीमा लगती है। कोराँव में कुल साक्षरता दर 2001 में 49.16 प्रतिशत था, जिसमें पुरुष साक्षरता 65.45 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 30.72 प्रतिशत था। पुरुष तथा महिला साक्षरता में कुल अन्तर 34.73 प्रतिशत देखा गया। वहीं 2011 में कुल साक्षरता 67.59 प्रतिशत है। 2011 में पुरुष साक्षरता 79.99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 65.09 प्रतिशत था, तथा इन दोनों में जो अन्तर देखा गया वह 25.9 प्रतिशत था।

जिससे यह पता चलता है कि कोराँव तहसील तथा विकासखण्ड में आज भी पुरुष तथा महिला साक्षरता में अन्तर देखने को मिलता है।

शोध के उद्देश्य

1. महिला साक्षरता की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन
2. सामाजिक और आर्थिक कारकों का प्रभाव

3. सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन

4. भविष्य की रणनीतियों का सुझाव

आँकड़ों का विश्लेषण

जनगणना 2001 और 2011 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कोराँव तहसील में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि पुरुष साक्षरता दर की तुलना में धीमी है। 2001 में कुल साक्षरता दर 49.16% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 65.45% और महिला साक्षरता मात्र 30.72% थी। उस समय पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर 34.73% था, जो क्षेत्र में गहरी लैंगिक असमानता को दर्शाता है। 2011 में कुल साक्षरता बढ़कर 67.59% हो गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.97% और महिला साक्षरता 54.09% थी। इस अवधि में लैंगिक अंतर घटकर 25.90% रह गया, जो सुधार की ओर इशारा करता है, लेकिन अब भी यह अंतर पर्याप्त रूप से कम नहीं हुआ है।

विकाखण्ड	साक्षरता							
	2001				2011			
कोराँव	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्तर	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्तर
	49.16	65.45	30.72	34.73	67.59	79.97	54.09	25.9

स्रोत: जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद, इलाहाबाद (2001, 2011)

आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता में सुधार के बावजूद, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी अधिक है। इसका प्रमुख कारण विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधा का अभाव, और परिवारों की आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताएँ हैं। कई परिवार अब भी यह मानते हैं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से बेहतर है कि वे घरेलू कार्यों में योगदान दें या शीघ्र विवाह कर लें। यह सोच न केवल महिला साक्षरता दर को सीमित करती है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की संभावनाओं को भी बाधित करती है।

जनगणना के आँकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सरकारी योजनाओं का कुछ सकारात्मक असर हुआ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे आवासीय स्कूलों ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा का अवसर दिया है। इसके अलावा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चलाए जा रहे साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रमों ने भी महिला साक्षरता में वृद्धि में योगदान दिया है। फिर भी, सरकारी प्रयास तब तक पूरी तरह सफल नहीं होंगे, जब तक स्थानीय समुदायों में शिक्षा के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता नहीं फैलाई जाती।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो महिला साक्षरता में वृद्धि से क्षेत्र में श्रमबल की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार आ सकता है। पढ़ी-लिखी महिलाएं न केवल अपने परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कर सकती हैं, बल्कि वे स्वयं भी स्वरोजगार, सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार, आँकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि महिला साक्षरता का सीधा संबंध क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास से है। यदि आने वाले वर्षों में लैंगिक अंतर को और कम किया जाए, तो कोराँव तहसील न केवल शिक्षा में बल्कि समग्र विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी बन सकती है।

निष्कर्ष

कोराँव तहसील में महिला साक्षरता का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि पिछले एक दशक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, किन्तु लैंगिक अंतर अब भी महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर में वृद्धि और पुरुष-महिला साक्षरता अंतर में कमी, यह दर्शाते हैं कि सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। फिर भी, यह प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक रूढ़िवादिता, गरीबी, शिक्षा संसाधनों की कमी और महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ हैं। महिला साक्षरता न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक प्रगति की आधारशिला भी है। पढ़ी-लिखी महिलाएँ अपने परिवारों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामुदायिक और क्षेत्रीय विकास में भी देखा जा सकता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जब तक स्थानीय स्तर पर शिक्षा के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता नहीं फैलाई जाती, तब तक सरकारी योजनाओं का प्रभाव सीमित रहेगा। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी, विद्यालयों की सुलभ उपलब्धता, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, तथा लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक मानसिकता आवश्यक है। अंततः, कोराँव तहसील में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना केवल एक शैक्षिक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और सतत विकास की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। यदि सरकार, समुदाय और परिवार मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास करें, तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ-

1. शर्मा, ए., & वर्मा, आर. (2019). ग्रामीण भारत में महिला साक्षरता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
2. सिंह, पी. के. (2020). प्रयागराज जिले में शिक्षा का भूगोल. वाराणसी: भारती प्रकाशन.
3. गुप्ता, एस. (2018). उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान.
4. मिश्रा, आर., & यादव, के. (2021). भारत में लैंगिक असमानता और शिक्षा. दिल्ली: ज्ञानदीप पब्लिकेशन्स.
5. चौधरी, एम. (2017). महिला सशक्तिकरण में साक्षरता की भूमिका: एक क्षेत्रीय अध्ययन. पटना: विद्या निकेतन.
6. Singh, B. B. (1979). Krishi Bhugol. Varanasi, India: Tara Publications.
7. National Informatics Centre. (2001). District Census Handbook: Allahabad District.
8. National Informatics Centre. (2011). District Census Handbook: Allahabad District.